आदिवासियों को अपनी जमीन के लिए हथियार उठाना पड़ेगा : गणेश घोघरा

डूंगरपुर का नाम डूंगरिया भील और माला कटारा के नाम करने की मांग उठाई

जयपुर (विसं)। विधानसभा में बुधवार को नगरीय विकास विभाग की अनुदान अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि आदिवासी कभी शहर की तरफ नहीं आया है, बल्कि शहर ही गांव की तरफ गया है और फिर कहते हो कि "ये नक्सली है," अगर जरूरत पड़ी तो अपने अधिकार के लिए यह हथियार भी उठाएगा। अपनी जमीन के लिए आदिवासियों को हथियार उठाना पड़ेगा।

घोघरा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का कोई मुख्य स्त्रोत नहीं है। आदिवासियों के पास एक और दो बीघा जमीन है। अपना जीवन यापन भी वे लोग मजदूरी करते हैं। घोघरा के इतना कहते ही बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई, जिस पर कुछ देर तक सदन में शोरगुल का माहौल बन गया।घोघरा ने कहा कि आदिवासी की छोटी जमीन भी कुछ लोग छीनना चाहते हैं। गेपसागर झील को नगर परिषद के आयुक्त और सभापति छीनना चाहते हैं। उन लोगों ने झील की जमीन पर प्लॉट काटकर भूमाफियाओं को बेच दिए। नाले का जो पानी आ रहा था, वह भी बंद कर दिया और प्लॉट काट कर बेच दिए। नगर परिषद डूंगरपुर में यह भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए।

घोघरा ने कहा कि डूंगरपुर का इतिहास डूंगरिया भील और माला कटारा के नाम से है। रात को माला कटारा का बोर्ड हटा दिया और वहां जय श्रीराम लिख दिया।

ऐसे में वहां कभी भी लोगों में आपस में संघर्ष हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। माला कटारा का बोर्ड वापस लगवाना चाहिए।

महिला विधायक को फटकार

जयपुर (विसं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को शून्यकाल में सदन में बात कर रहीं विधायक कल्पना देवी को फटकार लगा दी। बीजेपी विधायक को पहले तो स्पीकर ने धीरे से टोका, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। इस पर स्पीकर ने कल्पना देवी का नाम लेकर फटकार लगाई। दरअसल शून्यकाल में सदन की कार्यवाही के दौरान आपस में बात करने पर लाडपुरा विधायक कल्पना देवी को स्पीकर ने डांट दिया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, विधायक के पास जाकर समझाने लगे तो नेता प्रतिपक्ष ने फिर बातचीत को लेकर आपत्ति जताई। इस पर स्पीकर ने कहा कि वे तो उन्हें समझाने गए हैं।

सदन में सवाल पूछने की जगह लंबा ब्यौरा देने लगे निर्दलीय विधायक

स्पीकर ने टोकते हुए कहा, "भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए"

जयपुर (विसं)। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को पूरक सवाल पूछने की जगह लंबा ब्यौरा देने पर निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी को टोकते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि, आप भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए।

निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी पूरक सवाल के दौरान कहा कि जबसे सरकार आई है, हमारे किसानों को पानी मिल रहा है। कांग्रेस राज में तो 5 साल पानी नहीं मिला। हमारे यहां नहरी तंत्र में बारिश का ओवरफ्लो पानी बेकार जाता है। स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि सवाल पूछिए। यह भाषण हो रहा है। सवाल आप पूछ नहीं रहे। इस पर जीवाराम ने कहा कि आप इसे ही पूरक समझ लीजिए।

इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह बात सही है कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पिछले दो साल में अच्छी बारिश हुई है। उनका पगफेरा राजस्थान के लिए शुभ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा तो रावत ने कहा कि मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा। रावत ने निर्दलीय विधायक जीपराम चौधरी के सवाल के जवाब में कहा कि नर्मदा नहर परियोजना पर टेल के किसानों तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या के समाधान के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। जब 1.96 करोड़ की डीपीआर बन जाएगी तो बरसात के वक्त ओवरफ्लो होने वाले पानी का रिजर्वेयर बनाया जाएगा।

पैंशन को लेकर हरिमोहन शर्मा ने मंत्री अविनाश गहलोत पर कसा तंज

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बकाया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले को लेकर बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पर तंज कसा। हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सरकार ने 4 महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी, विधानसभा का सत्र चला तब बकाया पेंशन दी। खुशी की बात है, जिनके पास महकमे का चार्ज है, वह भी गहलोत है। एक गहलोत का तो सोच यह था कि किस प्रकार गरीबों का भला हो, दूसरे गहलोत का यह सोच कि चार महीने तक पेंशन भी नहीं दे। इसके अलावा जो नियमित रूप से पेंशन बढ़ानी चाहिए थी, उस हिसाब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बढ़ाई।

इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमने पहले ही साल सामाजिक सुरक्षा एक हजार से बढ़ाकर 1150 किया, फिर 1200 किया, अब 1300 रुपए किया है।

वॉकआउट

जयपुर। सामाजिक संस्थाओं के जमीन आवंटन में देरी को लेकर शून्यकाल में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले कांग्रेस विधायक मोतीराम ने रेवदर में तीन समाजों को छात्रावास के लिए जमीन आवंटन में देरी का मुद्दा उठाया। मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि रेवदर में जमीन आवंटन के तीनों मामले पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के फैसले हैं। आज ये कह रहे हैं कि कमियां है अलॉटमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ राजनैतिक फायदे के लिए निर्णय किया।

सिरोही में छात्रावासों के लिए भूमि होगी आवंटित : राजस्व मंत्री

जयपुर (विसं)। राजस्व मंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिले में विभिन्न समाजों के छात्रावास निर्माण के लिए नियमानुसार भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में नियमों की पूर्ण जांच-पड़ताल किए बिना ही भूमि आवंटन के निर्णय लिए थे, जिनमें लीज डीड सहित अन्य प्रशासनिक कमियां पाई गईं। इन कमियों के चलते प्रस्तावित आवंटन निरस्त कर दिए गए थे। राजस्व मंत्री ने आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार सभी प्रक्रियाओं की विधिवत जांच कर शीघ्र ही जमीन आवंटन की कार्रवाई शुरू करेगी। वे शून्यकाल के दौरान विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी नियम प्रक्रिया के तहत सामाजिक छात्रावासों के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन में देरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने शून्यकाल के दौरान सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले विधायक ने रेवदर क्षेत्र में तीन समाजों को छात्रावास हेतु भूमि आवंटन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया था।इस पर मंत्री हेमन्त मीणा ने कहा कि रेवदर के तीनों मामले पिछली सरकार के अंतिम छह महीनों में लिए गए निर्णयों से जुड़े हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली

इससे पूर्व भी 10 बार मिल चुकी है हाईकोर्ट को बम से उडाने की धमकी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। ई-मेल के जरिए दी गई इस धमकी में हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की की धमकी दी गई है। इससे पूर्व दस बार पहले भी यहां बम ब्लास्ट को लेकर धमकी भरे ई-मेल भेजे जा चुके हैं। मेल में धमकी दी गई कि 11 बजे तक हाईकोर्ट खाली कर दो, दोपहर डेढ़ बजे हाईकोर्ट में 18 बम धमाके होंगे। हालांकि अदालती समय आरंभ होने से पहले धमकी मिलने के चलते न्यायिक कामकाज प्रभावित नहीं हुआ और मुकदमों की सुनवाई शुरू होने के समय से पहले ही परिसर की जांच कर ली गई। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

इस पर दौरान जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की। जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन से राहत की सांस ली। आए दिन धमकी भरा मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसके चलते वकीलों में खासी नाराजगी है। वकीलों का कहना है कि कभी यह धमकी वास्तविक घटना में बदल गई तो जान-माल का नुकसान हो सकता है। हाल ही में साइबर सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में भी हाईकोर्ट को दी जा रही बम ब्लास्ट का मुद्दा उठ चुका है।

सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति में हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि जिस तरह स्कूल में रोजाना घंटी बजती है, उस तक हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकियां दी जाने लगी है। ऐसे में न्यायिक काम प्रभावित होता है, लेकिन यह ई-मेल कौन और कहां से कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन को सबसे पहले गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई। वहीं 8 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजे गए। इसके बाद गत छह फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई थी।

नए जिलों व तहसील के सवाल पर सदन में नोंकझोंक

जयपुर (विसं)। राजस्थान में नए जिलों और तहसील बनाने से जुड़े सवाल पर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कुछ देर के लिए सदन में हंगामे के हालात बन गए।

दरअसल कांग्रेस विधायक गीता बरवड़ के आसोप उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के मूल सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन और पुनर्गठन के लिए ललित के पवार कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद नई तहसीलों पर फैसला होगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए जिले को खालेंगे क्या? इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि "पिछली सरकार ने राजनैतिक लाभ के लिए नए जिले बनाए गए थे। जिले ले जाओ, तहसील ले जाओ और कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हमने लोगों की भलाई के लिए जिले-तहसील बनाए। आपने राजनीति करने के लिए बनाए।" राजस्व मंत्री की इस बात पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए कहा कि आप बना नहीं सकते। आप तो तोड़ सकते हो। इसी बीच स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया तो हंगामा शांत हुआ।

महाराजा गजसिंह द्वितीय से मिला एफ.एच.टी.आर. प्रतिनिधिमंडल

जयपुर। फैडरेशन ऑफ होस्पेटिलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने संघ के मुख्य संरक्षक एवं जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय से शिष्टाचार भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल में एफएचटीआर से प्रेसिडेंट ऑनर भीम सिंह, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह पचार, उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह राठौड़, महासचिव मधुवंती सिंह व तरूण बंसल, कार्यकारी संस्थापक सदस्य सीए वीरेन्द्र सिंह शेखावत एवं कार्यकारी सदस्य दीपेन्द्र राणा उपस्थित रहे। बैठक में राजस्थान में पर्यटन के समग्र विकास एवं भविष्य की रणनीतियों पर सकारात्मक एवं रचनात्मक चर्चा हुई।

बैठक का प्रमुख विषय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2026 की रूपरेखा एवं रणनीतिक योजना रहा। प्रतिनिधिमंडल ने आरडीटीएम को भारत के अग्रणी घरेलू पर्यटन मंच के रूप में और अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने की अपनी दृष्टि साझा की। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2026 में में एक विशेष ट्रैवल इवेंट आयोजित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य ब्लू सिटी को विरासत पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग्स एवं सांस्कृतिक अनुभव आधारित पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रतिनिधिमंडल ने इस आयोजन को मारवाड़ की शाही विरासत, सांस्कृतिक संरक्षण एवं उत्कृष्ट आतिथ्य परंपरा के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए महाराजा गजसिंह द्वितीय से मार्गदर्शन का अनुरोध किया। अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि महाराजा गज सिंह द्वितीय ने राजस्थान की अमूल्य विरासत के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक वैश्विक पर्यटन प्रवृत्तियों के अनुरूप आगे बढ़ने के महत्व पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।